''फोर्ट विलियम कालेज की भाषा-नीति''

डॉ. रवींद्रनाथ मिश्र

प्रस्तुत विषय में दो शब्द भाषा और नीति अर्थ-व्यक्ति की दृष्टि से काफी व्यापक एवं महत्वपूर्ण हैं । भाषा समाज में विचार-विनिमय का साधन है । हमारे विचारों की वाहिका है । संस्कृति का अभिन्न अंग और व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के विकास में सहायक भी है । इस प्रकार ढेरों सारी बातें भाषा से संबंधित हैं । अत एव भाषा के संबंध में ठोस और स्वस्थ नीति का निर्धारण करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा इतिहास गवाह है कि इससे अनेक समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं और विकास की गति को धक्का लगा है और लग रहा है । यह बात जरूर है कि नीति निर्धारण की प्रक्रिया बहुत जटिल और महत्वपूर्ण होती है। जब विचारों का महल नीतियों पर खड़ा होता है तो वह सहज और सर्वसमावेशी होता है । अगर इसमें थोड़ी सी असावधानी बरती गई तो भविष्य में यह बहुत बड़े संकट का कारण बन सकती है । जैसा कि फोर्ट विलियम कालेज की भाषा-निति के संदर्भ में हुआ ।

आइए अब फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना की पृष्ठभूमि के संबंध में बात करते हुए भाषा-निति पर विचार करें ।

19 वीं शती का समय राजनीतिक, सामाजिक सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्यिक पुनर्जागरण का युग था जिसमें अनेक क्षेत्रों में क्रांतिकारी घटनाएँ घटित हुईं, जिसका प्रभाव तत्कालीन युग पर पड़ा । हमारे यहाँ मुगलकाल से ही यूरोपियों का आना-जाना शुरू हो गया था, जिनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करने का था । परंतु कालांतर में ये व्यापारी से प्रशासक बन गए । ब्रिटिश सत्ता ने भारत में अपना शासन तीन चरणों में पूरा किया ।

सन् 1600 ई॰ से 1757 ई॰ तक व्यपारी के रूप में । इस काल

में ही सन् 1600 ई॰ में अंग्रेजों द्वारा व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई । सन् 1709 ई॰ से 1757 ई॰ तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनेक व्यापारिक सफलताएँ प्राप्त कीं । बंबई, मद्रास और कलकत्ता तीन प्रमुख व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की गई । सूरत, आगरा और अहमदाबाद में फैक्टरियों की स्थापना हो गई । चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज के रूप में मिल गया था । कालांतर में कंपनी को सेना संचालन, युद्ध और संधि करने का भी अधिकार दिया गया।

सन् 1757 ई॰ से 1857 ई॰ तक का समय साम्राज्य विस्तार और 1857 से 1947 तक का समय शासन व्यवस्था की स्थापना का रहा ।

यहाँ हम द्वितीय चरण की बात करेंगे, जिसमें कि कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन् 1800 ई॰ में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना की गई । इस कालेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कंपनी के कर्मचारियों को देशी-भाषाओं का ज्ञान कराना तथा उसके लिए भाषा-नीति का निर्धारण करना ।

इसके पूर्व भारत में शिक्षा की इंग्लैण्ड से बेहतर व्यवस्था भी और उच्च शिक्षा के केंद्रों की संख्या वहाँ से अधिक थी । शिक्षा का भार स्थानीय लोगों पर था । सरकार पर वह बिल्कुल अवलंबित नहीं थी। पाठ्यक्रम ऐसे थे कि शासन, लोक-व्यवहार, शिल्प, कला-कैशल्य, आयुर्वेद, ज्योतिष और हिसाब-किताब ये पूर्ण शिक्षा के अंग थे । शिक्षित व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करता था । उस समय संस्कृत, फारसी और स्थानीय भाषा का ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग था । शिक्षण का बहुत बड़ा हिस्सा वाचिक था । समाज में शिक्षण का बहुत सम्मान था । इस प्रकार हिंदुस्तानी शिक्षा-पद्धति में एक ऐसी तेजस्विता थी, जिसे कंपनी सरकार तो सह सकती थी क्योंकि वह रोजगारी थी परंतु वह अपने सरकारी लोगों का दिल ऊपर से नहीं दुखाना चाहती थी । कंपनी के शासन की स्थापना के बाद भारत में प्रमुख

भाषाएँ इस प्रकार थीं ।

1. अंग्रेजी भाषा जो कंपनी की अपनी भाषा थी ।
2. फारसी जो कि मुस्लिम शासन काल से देश की राजभाषा चली आ रही थी ।
3. देशी भाषाएँ जो क्षेत्रीय भाषाएँ थीं और जिसमें हिंदी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था । अंग्रेजी कंपनी सरकार की अपनी भाषा थी जिसे वह राजभाषा बनाना चाहती थी । आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की जानकारी हेतु कुछ भारतीय भी अंग्रेजी शिक्षा पर विशेष जोर देने लगे । फारसी भाषा की स्थिति उस समय बहुत विचित्र थी । वह मुसलमानों के शासन काल से राजभाषा अवश्य थी लेकिन सर्वसाधारण की भाषा नहीं थी । जहाँ तक देशी भाषाओं का सवाल है उनमें हिंदी सबसे लोक प्रचलित लोकभाषा थी । कंपनी सरकार राजभाषा संबंधी अपनी नीति का निर्धारण करना चाहती थी । चूँकि कंपनी की भाषा अंग्रेजी थी, इसलिए वह अंग्रेजी को ही शासन की भाषा बनाना चाहती थी। किंतु उसके सामने समस्या यह थी कि दिल्ली दरबार की भाषा फारसी थी और तत्कालीन लोकप्रचलित भाषा हिंदी थी । इसलिए कंपनी ने अपनी चतुरतापूर्ण नीति को अपनाते हुए फारसी के साथ-साथ हिंदी के प्रयोग को भी जारी रहने दिया । कंपनी शासन के कार्यों में दोनों भाषाओं का प्रयोग करती थी।

किसी भी देश को अपनी शासन-व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए सशक्त भाषा की आवश्यकता होती है, जिसमें कि विचारों का आदान-प्रदान सरलता से हो सके तथा वह शिक्षा, साहित्य और प्रशासन के कार्यों के उपयुक्त हो । इस दिशा में शुरू में कंपनी के अधिकारियोंने ध्यान नहीं दिया । सन् 1798 ई॰ में जब लार्ड वैलेजली भारत आए तो उन्होंने यह अनुभव किया कि कंपनी के कर्मचारी केवल एक व्यापरिक संस्था के कर्मचारी ही नहीं बल्कि अब एक सरकार के अधिकारी हैं। उनमें शिक्षा, जनभाषा का ज्ञान और सदाचार की आवश्यकता है । वे

कंपनी को एक राजनीतिक एवं सुदृढ़ संस्था बनाना चाहते थे । इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना की ।

राजनीतिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के अतिरिक्त इस कालेज की स्थापना से भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदी, बंगला और उर्दू को बहुत प्रोत्साहन मिला । यह कालेज सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी विषयों का प्रधान केंद्र बन गया । कालेज की भाषा-नीति का निर्धारण करते समय इस बात पर जोर दिया गया कि आधुनिक भारतीय भाषाओं को वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप दिया जाए । इसके लिए कालेज की गतिविधियों को दो भागों में विभक्त किया गया - शिक्षण - संबंधी और भाषा-संबंधी।

इस कालेज में पूर्वी और पश्चिमी साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंग्रेजी कानून, हिंदी कानून, नीति विज्ञान तथा नागरिक-शासन के अंतर्गत आने वाले विधानऔर नियम, अर्थ-शास्त्र, भूगोल, गणित, प्रकृति विज्ञान, वनस्पतिशास्त्र, रसायन शास्त्र तथा नक्षत्र विज्ञान आदि सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी । इस कालेज में अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदुस्तानी, बंगला, तेलगु, मराठी, तमिल, कन्नड, मलयालम और सभी भारतीय भाषाओं को पढ़ाने की व्यवस्था भी थी । यहाँ से अनेक भारतीय भाषाओं में विशेषत: फारसी, बंगला, अरबी और हिंदुस्तानी में अनेक ग्रंथ प्रकाशित किए गए ।

उपर्युक्त व्यवस्था के प्रति अंग्रेजों की भाषा-नीति स्पष्ट रूप से झलकती है कि वे लगभग सभी भारतीय भाषाओं को विकसित करना चाहते थे । अंग्रेजी के साथ-साथ भारतीय भाषाओं के अध्ययन और अध्यापन की सुविधा भी प्रदान की गई । इस भाषा-नीति के पीछे उनका राजनीतिक और प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति का स्वार्थ छिपा हुआ था।

सर जान गिलक्राइस्ट को हिंदी-उर्दू का अध्यापक नियुक्त किया

गया। ये हिंदुस्तानी विभाग के सर्वप्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए । इनके अतिरिक्त डॉ. कैरे, कोलब्रुक तथा पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे महान विद्वान अध्यापक थे । जान गिल क्राइस्ट ने हिंदी और-उर्दू की पुस्तकें तैयार करने के लिए तथा अध्ययन एवं अध्यापन के लिए पंडित सदल मिश्र, लल्लूलाल, श्री सदासुख और इंशा अल्लाखाँ को नियुक्त किया । गिलक्राइस्ट के अनुसार हिंदुस्तानी की तीन शैलियाँ थीं । दरबारी फारसी शैली, विशुद्ध हिंदुस्तानी शैली और हिंदवी शैली । वे फारसी शैली को दुरूह तथा हिंदवी शैली को गंवारु मानते थे । इन तीनों में उन्होंने विशुद्ध हिंदुस्तानी शैली को प्रथमिकता दी । गिलक्राइस्ट के अनुसार हिंदवी, अरबी-फारसी का मिश्रित रूप ही हिंदुस्तानी है । परंतु उनकी यह हिंदुस्तानी वस्तुत: उर्दू ही है । उन्हीं की प्रेरणा से उर्दू परिपूर्ण होकर फारसी के स्थान पर सरकारी भाषा बनने के योग्य बनी।

गिलक्राइस्ट की भाषा-नीति में सभी भाषाओं में उर्दू को विशेष महत्व दिया गया । यह मात्र मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए किया गया । इस नीति का परिणाम यह हुआ कि भाषा के सवाल को लेकर अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुईं ।

फोर्ट विलियम कालेज की भाषा नीति से शुरू में हिंदी को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ लेकिन गद्य लेखन पर अधिक जोर दिया गया। यहीं से गद्य का वास्तविक रूप उदय हुआ । कालांतर में शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और शासन के कार्यों के लिए गद्य की विशेष आवश्यकता महसूस की गई । इसके लिए अनेक हिंदी-उर्दू के अध्यापकों की नियुक्ति की गई, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है।

कालेज की भाषा-नीति में इस प्रकार की व्यवस्था से भाषाओं को फलने-फूलने का अवसर मिला । इसके बाद में हिंदी को काफी लाभ हुआ। लिपि के संबंध में जान गिलक्राइस्ट ने पक्षपातपूर्ण नीति का समर्थन किया । ये रोमन और फारसी लिपि के पक्ष में थे । लेकिन नागरी लिपि

का बहिष्कार भी नहीं कर पाए । उनका विचार था कि हिंदुस्तानी का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए फारसी भाषा और लिपि का ज्ञान आवश्यक है । वे स्वयं अरबी-फारसी भाषाओं के विद्वान थे । गिल क्राइस्ट की पक्षपातपूर्ण भाषा-नीति का हिंदी के प्रचार प्रसार पर बुरा प्रभाव पड़ा ।

कालेज की व्यवस्था में भाषा मुंशी और पंडितों का स्थान सदैव गौण रहा । उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं समझी जाती थी ।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1800-1804 ई० तक गिल क्राइस्ट की भाषा-नीति बहुत ही भ्रामक रही । सन् 1804 ई० में उनके कालेज छोड़ने के बाद भी भाषा संबंधी भ्रान्तिपूर्ण नीति जारी रही । सन् 1823 ई० में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में प्राइस की नियुक्ति हुई । उस समय तक कालेज में हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी अध्ययन का कार्य प्रारंभ हो चुका था । विलियम प्राइस अपने को हिंदी प्रोफेसर कहते थे और हिंदी और हिंदुस्तानी में लिपि और शब्दों का मुख्य अंतर मानते थे। प्राइस की भाषानीति से कालेज के संचालकों को भी अपनी भाषा-नीति में परिवर्तन करना पड़ा । इनके द्वारा गिल क्राइस्ट की भ्रामक भाषा-नीति को सुधारने का प्रयत्न किया गया । प्राइस के बाद कालेज की गतिविधियों में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई । सन् 1854 ई० में कालेज बंद कर दिया गया ।

वस्तुत: कालेज की भाषा-नीति के जरिए हिंदी और उर्दू के बीच दूरी पैदाकर अंग्रेजी भाषा और रोमन लिपि को स्थापित किया गया । हिंदुस्तानी के नाम पर उर्दू को जो प्रश्रय और प्रोत्साहन मिला, उससे भाषा को लेकर बाद में बहुत विवाद खड़ा हुआ । अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता को उभारने के लिए देश पर उर्दू को लादने का प्रयास किया । भाषा-नीति के दुष्परिणाम के संदर्भ में डॉ. सरनाम सिंह शर्मा के विचार इस प्रकार हैं -

"अंग्रेजी शासन की स्थापना से भाषा के क्षेत्र में एक विस्फोट

भावना का प्रजनन हुआ । धर्म की आड़ में कूटनीतिक चालों को घोषित करने का अवसर लेकर शासकों ने अपना उल्लू सीधा करने की चेष्टा की। उन्होंने हिंदुस्तानी शब्द से एक ऐसे विष का प्रादुर्भाव किया, जो बढ़ता और फैलता गया । हिंदी और उर्दू के संबंध में उससे एक निश्चित भेद-दृष्टि हो गई ।''

क्राइस्ट द्वारा हिंदुस्तानी विभाग में हिंदी-उर्दू को अलग-अलग भाषा मानकर उनके लिए अलग-अलग पंडितों और मुंशियों की नियुक्ति की ।इससे आगे चलकर सांप्रदायिक भावना को बल मिला । भाषा को संप्रदाय से जोड़ दिया गया, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि आजादी के सैंतालीस वर्षों के बाद भी देश सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा है ।

भाषा-नीति के सकारात्मक पक्ष की बात करें तो जिस प्रकार कालेज में लगभग सभी भारतीय भाषाओं के अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था की गई उसका प्रभाव दूरगामी रहा । कालंतर में हिंदी और अन्य भाषाओं को विकसित होने का अवसर मिला । पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव के कारण हमारी सोच और समझ में बदलाव आया जिसका प्रभाव साहित्य पर पड़ा ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि फोर्ट-विलियम कालेज की भाषा-नीति का प्रभाव कालांतर में तिक्त एवं मधुर दोनों रहा ।

हिंदी विभाग
गोवा विश्वविद्यालय,
गोवा - 403 203